राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

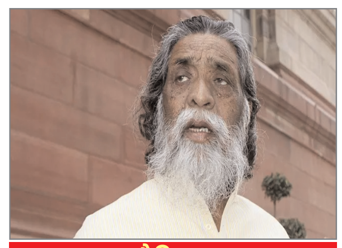

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 04 फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 285, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

वन विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से फलफूल रहा है अवैध लकड़ी कटान का व्यापार..03

अमेरिका के हमले का जरा भी खौफ नहीं, खुमैनी के मकबरे से दहाड़े खामनेई..04

भारत से निकल जाएं... भरे सुप्रीम कोर्ट में भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत, वॉट्सऐप को दे दी वॉर्निंग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वॉट्सऐप-मेटा डेटा शेयरिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद रुख अपनाते हुए बड़ी चेतावनी दी है. सीजेआई सूर्यकांत ने नागरिकों की निजता को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी Meta से दो टूक कहा कि नागरिकों की निजता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. अगर कोई कंपनी देश के संविधान और कानूनों का पालन नहीं कर सकती, तो उसके लिए विकल्प बहुत स्पष्ट है... भारत से बाहर निकल जाए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से बेहद सख्त लहजे में कहा, 'हम आपको एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे. आप इस देश के नागरिकों के अधिकारों से नहीं खेल सकते. यह संदेश आपके वॉट्सऐप को भी साफ तौर पर जाना चाहिए।'

सीजेआई सूर्यकांत ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत चालाकी से इस तरह तैयार की गई है कि आम यूज़र भ्रमित हो जाए. उन्होंने कहा, 'आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह बनाई गई है कि कोई गरीब, बुजुर्ग या महिला, जो सड़क पर सब्ज़ी बेचती हो, या जो केवल तमिल समझती हो, या जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हो, वह आपकी मंशा को आखिर कैसे समझ पाएगी?'

डेटा प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

WhatsApp-Meta डेटा शेयरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ किया कि निजता का अधिकार कोई विकल्प नहीं, बल्कि संविधान से मिला मौलिक अधिकार है. अदालत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीजेआई सूर्यकांत ने तीखे शब्दों में सवाल किया, 'क्या यह कोई विकल्प है कि आप वॉट्सएप सेवा से बाहर निकल जाएं और फिर भी आपका डेटा साझा किया जाए? विकल्प बहुत सरल है... या तो आप स्पष्ट अंडरटेकिंग दें या हम एक शब्द भी डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देंगे।'

मेटा ने क्या दी दलील?

वहीं मेटा की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से लगाया गया जुर्माना जमा कर दिया गया है, हालांकि मामला अपील के अधीन है. उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं के पास ऑप्ट-आउट का विकल्प मौजूद है और 15 नवंबर के आदेश से जुड़े निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

इस पर CJI ने सख्त लहजे में कहा कि ऑप्ट-आउट जैसे विकल्प नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकते. अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में डेटा शेयरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ कई अहम निर्देश जारी किए

सभी अपीलों को तीन जजों की पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इस पर काउंटर दलील चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

CCI की तरफ से मेटा पर लगाया गया जुर्माना जमा रहेगा, लेकिन अगले आदेश तक राशि की निकासी पर रोक रहेगी।

अगली सुनवाई पर टिकी नजर

अब यह मामला तीन-सदस्यीय पीठ के सामने जाएगा, जहां डेटा गोपनीयता, टेक कंपनियों की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से यह साफ संकेत मिल गया है कि भारत में काम करने वाली किसी भी टेक कंपनी को संविधान, कानून और नागरिकों की निजता का पूरा सम्मान करना ही होगा, वरना अदालत पीछे हटने वाली नहीं है।

'शादी डॉट कॉम' के संस्थापक अनुपम मित्तल को SC से राहत, 2 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'शादी डॉट कॉम' के संस्थापक अनुपम मित्तल और दो अन्य की गिरफ्तारी पर दो हफ्ते की रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अंतरिम जमानत के लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाना होगा. यह मामलाइस वैवाहिक वेबसाइट के एक उपयोगकर्ता द्वारा कथित धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारी की बेंच ने की.सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मित्तल के खिलाफ कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया गया था और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यह अंतरिम जमानत का मामला है, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए।

क्या है मामला

दरअसल यह मामला हैदराबाद की एक महिला की शिकायत से जुड़ा है. महिला का आरोप है कि उसने शादी डॉट कॉम पर एक प्रोफाइल के जरिए संपर्क किया.संबंधित व्यक्ति ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया और उससे करीब 11 लाख रुपये की

धोखाधड़ी की गई. महिला का आरोप है कि वेबसाइट ने यूजर के विवरण का सही तरीके से वैरिफिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से यह धोखाधड़ी संभव हो सकी।

अनुपम मित्तल का तर्क

इस शिकायत के आधार पर दर्ज केस में शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल और अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हुई. मित्तल ने तर्क दिया कि प्लेटफॉर्म केवल एक जरिया है. उन्होंने कहा कि किसी एक यूजर की आपराधिक हरकत के लिए कंपनी या फाउंडर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. इसी के खिलाफ उन्होंने पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने मित्तल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मित्तल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि निर्णय विवाद के मूल कानूनी तथ्यों के आधार पर नहीं लिया गया, इसलिए हम उक्त आदेश को निरस्त करते हैं और मामले को इसके मूल तथ्यों के आधार पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट को वापस भेजते हैं. आपराधिक मामलों को उनकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है. हाई कोर्ट इनके मूल कानूनी तथ्यों के आधार पर विचार करेगा. यह कोर्ट इस संबंध में कोई राय नहीं दे रहा. बेंच ने कहा कि इस बीच, याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट के समक्ष अनुरोध कर सकता है।

मित्तल के वकील ने कही ये बात

अनुपम मित्तल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील आत्माराम नाडकर्णी ने दलील दी कि वह एक वैवाहिक वेबसाइट संचालित कर रहे हैं, जो जीवनसाथी ढूंढने में मदद करता है. उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ जीवनसाथी ढूंढने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं. लेकिन फिर मुझे आरोपी क्यों बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ने 26 जून को तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.पिछले साल तेलंगाना हाई कोर्ट ने मित्तल और दो अन्य आरोपियों, विग्नेश और सतीश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

संक्षिप्त ख़बरें

गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट केस में एक्शन, 8 दारोगा लाइन हाजिर; इनकी ही ID का हुआ था इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में 8 एसआई को लाइन हाजिर किया गया है. वहीं पासपोर्ट प्रकरण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं जिन दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह 90 के दशक में अफगानिस्तान से भारत आए हैं और वो लोग ही लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनवा रहे थे. प्रत्येक पासपोर्ट के लिए 1 से 2 लख रुपए की रकम ली जाती थी. यह जानकारी भी आज गाजियाबाद पुलिस ने मीडिया से साझा की है. जानकारी के मुताबिक एक खान नाम का शख्स भी इसमें शामिल है जो पासपोर्ट के खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. उसे गिरफ्तार करने के पुलिस प्रयास कर रही है. गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के एक ही गांव में फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में 8 एसआई को लाइन हाजिर किया है इसकी वजह पकड़े गए और निलंबित हुए कांस्टेबल के द्वारा उनकी आईडी का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है. मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लापरवाही के कारण इनको लाइन हाजिर किया गया है. इसके साथ ही इनकी अभी जांच आगे भी की जा रही है. अगर इनमें से कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कर रही जांच

भोजपुर थाना क्षेत्र के त्योडी गांव को ही आरोपियों ने क्यों चुना? इसकी भी कहानी पुलिस ने बताई है. मुख्य आरोपी जब हाईवे से गुजरा करता था तो उसकी नजर अक्सर इस गांव पर पढ़ती थी जिसकी वजह से उसने इस गांव को अपना ठिकाना बना लिया और इसी के पत्ते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने लगा. हालांकि पुलिस की इस बात में कितने सच्चाई है यह तो अन्य आरोपियों के पकड़े जाने और पूरी जांच हो जाने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर गाजियाबाद का नाम कलंकित कर दिया है. आरोपी पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारी और पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगा गए हैं. इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हो कैसे गई इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में 8 एसआई लाइन हाजिर किए गए हैं, जिनकी उपस्थित संदिग्ध मानी जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि जांच की जा रही है, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कुलदीप सिंह सेंगर केसः अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है. सेंगर ने उन्नाव कस्टोडियल मौत मामले में अपनी 10 साल की सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी है।

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा और दोषसिद्धि को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले की सुनवाई 11 फरवरी को सूचीबद्ध की. यह प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई होगी. पीठ ने 11 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया है।

रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई थी मौत

कोर्ट ने माना कि चूंकि सेंगर की सजा को निलंबित करने की याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और अपील के निपटारे में देरी हो रही है, इसलिए न्याय के हित में मुख्य अपील

पर रोजाना सुनवाई करना जरूरी है. सेंगर की ओर से वकील कन्हैया सिंघल कोर्ट में पेश हुए. वहीं सीबीआई की ओर से वकील अनुभा भारद्वाज पेश हुई. यह मामला उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है।

10 साल की सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती

कुलदीप सिंह सेंगर ने तीस हजारी कोर्ट से मिली 10 साल की सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट में दी है.इससे पहले सेंगर की सज़ा निलंबित करने की याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है.कोर्ट का मानना रहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती. कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में मौत जैसे गंभीर अपराध में जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाई

इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था. इस आदेश के बाद मामला गरमा गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी. सजा निलंबन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के मामले में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती. कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसे मामलों में समाज और न्याय व्यवस्था को कड़ा संदेश देना जरूरी है. इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. सभी को पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाया गया था.अपनी दलील में कुलदीप सिंह सेंगर ने कोर्ट को बताया था कि वह करीब 9 साल की सजा पहले ही काट चुका है और उसकी केवल 11 महीने की सजा बाकी है. हालांकि, पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि सेंगर को रिहा किए जाने से पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

संसद में विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र पर धब्बा... राहुल का ओम बिरला को खत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संसद में पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब (अनपब्लिश्ड) पर रार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के कहने पर मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है. देश की सुरक्षा पर मुझे बोलने से रोका जा रहा है।

राहुल ने कहा कि सदन में सभी सांसदों को बोलने का अधिकार है. राहुल ने कहा कि नेता विपक्ष को जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है. ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है. राहुल ने कहा कि संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया हो।

स्पीकर को लिखी चिट्ठी में राहुल ने क्या कहा?

ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, आपने मुझे उस मैगजीन को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा था, जिसका मैं जिक्र करना चाहता था. आज अपना भाषण फिर से शुरू करते समय मैंने उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर दिया. संसदीय नियमों और पुरानी परंपराओं के मुताबिक, अगर कोई सदस्य सदन में किसी दस्तावेज का हवाला देना चाहता है, तो उसे उसकी सत्यता की जिम्मेदारी लेनी होती है. एक बार यह जिम्मेदारी लेने के बाद, स्पीकर उसे वह दस्तावेज पढ़ने या उसका जिक्र करने की अनुमति देते हैं. इसके बाद उस मुद्दे पर जवाब देना सरकार का काम है, न कि स्पीकर का।

मुझे बोलने से रोकना परंपरा का उल्लंघन

पत्र में आगे कहा गया है कि आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना न सिर्फ इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के भाषण का एक अहम हिस्सा था, जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. इसलिए विपक्ष के नेता के तौर पर इस पर चर्चा करना मेरा अधिकार और कर्तव्य है।

संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

राहुल ने पत्र में आगे कहा कि सदन के निष्पक्ष संरक्षक के तौर पर हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करना आपकी संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल हैं. विपक्ष के नेता और हर सदस्य का बोलने का अधिकार हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है. संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के कहने पर स्पीकर को विपक्ष के नेता को बोलने से रोकना पड़ा है. यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है. इसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं।

सीटेट परीक्षाओं के बीच में डायट ने आईसीटी प्रशिक्षण का किया आयोजन , मुश्किल में शिक्षक, शिक्षकों ने प्रशिक्षण टालने की किया माँग

बस्ती। बस्ती जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्ती द्वारा सीटेट परीक्षाओं के बीच में शिक्षकों हेतु आईसीटी प्रशिक्षण का आयोजन करके शिक्षकों को अचानक मुश्किल में डाल दिया है जिसकी चर्चा पूरे जनपद में शुरु हो गयी है और आदेश से नाराज शिक्षकों ने प्रशिक्षण को टालने की माँग किया है ।सूच्च है कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन आगामी 07 व 08 फरवरी 2026 को सुनिश्चित है और समस्त ऐसे शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं जो अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य हो गयी है जिसके कारण पात्र व जरूरत मंद शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं । इसी बीच जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षको हेतु दिनाँक 04 फरवरी से आईसीटी प्रशिक्षण का आयोजन कर शिक्षकों हेतु नयी मुसीबत पैदा कर दिया है । शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि आखिर वे स्कूल देखें या अपने परीक्षा की तैयारी करें या पूरा - पूरा दिन डायट में बैठकर प्रशिक्षण लें । नाम न छापने की शर्त पर कुछ शिक्षकों ने ही बताया कि डायट का यह कृत्य कदापि समयानुकूल नहीं है जनहित व शिक्षक हित में प्रशिक्षण तिथियों में बदलाव जरूरी है बेहतर होता यदि प्रशिक्षण का आयोजन सीटेट परीक्षाओं के बाद होता।

निजी संपत्ति में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना आयोजित करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. उच्च न्यायालय दो ईसाई निकायों- 'मारानाथा फुल गोस्पेल मिनिस्ट्रीज' और 'एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट' की एक जैसी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें निजी परिसरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी. बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब का संज्ञान लेने के बाद उक्त आदेश पारित किया. राज्य सरकार ने बताया कि कानून में अनुमति लेने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अदालत ने कहा, 'राज्य सरकार के जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि निजी परिसरों में धार्मिक प्रार्थना आयोजित करने को लेकर याचिकाकर्ताओं पर कोई रोक नहीं है.' सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी निकायों द्वारा राज्य भर के सभी नागरिकों को धर्म या किसी अन्य

आधार पर भेदभाव किए बिना कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा रहे इस कार्य को करने के लिए कानून के तहत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह इस शर्त के अधीन है कि धार्मिक प्रार्थना सभा केवल संपत्ति के निजी परिसर के भीतर ही आयोजित की जाए. अदालत ने आगे कहा, 'हालांकि, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां प्रार्थना सभा को सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति पर करना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को कम से कम पुलिस को सूचित करने और यदि आवश्यक हो तो कानून के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने का आदेश देता है.' गौरतलब है कि बीते 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली ज़िले के एक गांव से 12 लोगों को बिना आधिकारिक अनुमति के खाली पड़े मकान में नमाज अदा करने के आरोप में हिरासत में लिया था. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह संपत्ति हनीफ नामक व्यक्ति की थी और 16 जनवरी को शुक्रवार की नमाज के लिए इसका अस्थायी रूप से उपयोग किया गया था. पुलिस ने बताया कि पूछताछ करने पर वहां मौजूद लोग कोई लिखित अनुमति या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. हालांकि मकान मालकिन ने मीडिया को बताया था कि उनका घर खाली पड़ा था और उन्होंने ही स्थानीय लोगों को अपने घर में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी।

ये नेक्स्ट जेनरेशन, दिल्ली और देश की तरक्की का रोडमैप... बजट पर बोले मंत्री प्रवेश सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 202627 को नेक्स्ट जेनरेशन बजट बताते हुए कहा कि यह बजट भारत की आर्थिक नींव को और मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली के विकास को नई रफ्तार देगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत आज एक विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है. इसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय व्यापार फैसलों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे में साफ दिखाई देता है. अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किए जाने के फैसले पर प्रवेश ने इसे भारत के लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह भारत की मजबूती, स्थिरता और विकास क्षमता पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है. यह साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और भरोसेमंद वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है. इससे हमारे निर्यातकों को लाभ मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे।

आने वाले भारत के निर्माण के लिए है बजट

इस वैश्विक सकारात्मक माहौल को केंद्रीय बजट 202627 से जोड़ते हुए मंत्री ने कहा, सरकार की आर्थिक सोच तात्कालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है. यह बजट आज के फायदे के लिए नहीं बल्कि आने वाले भारत के निर्माण के लिए है. यह 2047 तक विकसित भारत और उसके साथ विकसित दिल्ली का रोडमैप तैयार करता है. दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रवेश ने बताया, चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग को सड़क विकास के लिए 805 करोड़ मिले हैं. जबकि 202627 के लिए विभाग केंद्र सरकार से लगभग 1,200 करोड़ की केंद्रीय सहायता और आवंटन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा. इससे बड़े पैमाने पर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के काम किए जाएंगे. इस बढ़ी हुई केंद्रीय मदद से राजधानी में सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

तेजी से आगे बढ़ रही हैं परियोजनाएं

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय से परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. कई वर्षों से लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य अब पूरी गति से पूरे हो रहे हैं. शासन व्यवस्था में सुधारों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 11 महीनों में स्थिरता, जवाबदेही और कार्यकुशलता आई है, जिससे रुकी हुई विकास योजनाएं फिर से शुरू हो सकी हैं. प्रवेश ने कहा कि पहले राजनीतिक टकराव के कारण दिल्ली का विकास बार-बार रुकता था. आज काम फोकस, पारदर्शिता और गति के साथ आगे बढ़ रहा है. वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है. मजबूत नेतृत्व, बढ़ता वैश्विक विश्वास और दूरदर्शी नीति मिलकर भारत और दिल्ली दोनों का एक शक्तिशाली भविष्य गढ़ रहे हैं।

रक्षा खर्च नहीं, राष्ट्रीय निवेश: भारत की शक्ति-निर्माण यात्रा

[शक्ति का लोकतंत्रीकरण: स्वदेशी भारत]

[हथियार नहीं, आत्मविश्वास खरीदा गया है इस बजट में]

इतिहास के कुछ क्षण केवल घटित घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बाद लिए गए निर्णायक फैसलों से अमर होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण विजय के तुरंत बाद प्रस्तुत 7.85 लाख करोड़ का रक्षा बजट ऐसा ही एक निर्णायक क्षण है। यह बजट मात्र व्यय का विवरण नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई सामरिक दृष्टि, अडिग आत्मविश्वास और भविष्य की सशक्त तैयारी का स्पष्ट उद्घोष है। 15% की यह वृद्धि साफ संकेत देती है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा किसी समझौते की नहीं, बल्कि सामर्थ्य, संकल्प और निर्णायक शक्ति की भाषा में परिभाषित होगी। पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ की तुलना में यह वृद्धि असाधारण अवश्य है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह अनिवार्य भी है। विशेष रूप से पूंजीगत व्यय का 2.19 लाख करोड़ तक पहुंचना और उसमें 22% की तेज छलांग यह दर्शाती है कि भारत अब तात्कालिक जरूरतों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक शक्ति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युद्ध में तकनीक, तैयारी और आत्मनिर्भरता ही विजय की कुंजी होती हैं। इसी कारण यह बजट आंकड़ों से आगे बढ़कर एक सशक्त रणनीतिक संदेश बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस निर्णायक ढंग से दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया, उसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की परंपरागत धारणाओं को बदल दिया। शत्रु ठिकानों का सटीक और प्रभावी विनाश तथा संघर्षविराम के लिए विवश करना केवल सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक चेतावनी थी। अब यह बजट उसी चेतावनी को स्थायी सामरिक शक्ति में रूपांतरित करने का साधन बन रहा है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म, प्रत्येक प्रणाली और प्रत्येक हथियार को स्वदेशी बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम है।

रक्षा मंत्री द्वारा इसे 'रणनीतिक अनिवार्यता' करार देना वर्तमान वैश्विक यथार्थ की सटीक और स्पष्ट व्याख्या है। मई 2025 के सीमित किंतु तीव्र संघर्ष ने यह उजागर कर दिया कि आतंक और अस्थिरता की जड़ें पड़ोसी भूभागों में गहराई तक फैली हुई हैं। ऐसे वातावरण में केवल रक्षात्मक रुख पर्याप्त नहीं, बल्कि आक्रामक, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति की नितांत आवश्यकता है। इसी रणनीतिक सोच के अनुरूप इस बजट में विमानन, एयरो इंजन और अगली पीढ़ी की युद्ध प्रणालियों पर विशेष और स्पष्ट बल दिया गया है। विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ तथा नौसेना के बेड़े के लिए 25,023 करोड़ का आवंटन भारत की बहु-आयामी और संतुलित सैन्य तैयारी का स्पष्ट संकेत है। अगली पीढ़ी के फाइटर जेट, एईडब्ल्यू एंड सी प्रणालियां, एमएलआरएस, बीवीआर मिसाइलें और लोइटरिंग मुनिशन्स अब कागजी योजनाएं नहीं, बल्कि ठोस अधिग्रहण की प्राथमिक सूची में शामिल हो चुके हैं। कुल पूंजीगत बजट का 75% घरेलू उद्योग से खरीद के लिए निर्धारित किया जाना आत्मनिर्भर भारत की नीति को विचार से निकालकर ठोस जमीन पर स्थापित करता है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि सशक्त और स्थापित वास्तविकता का रूप ले चुका है। 1.39 लाख करोड़ से बढ़कर 1.64 लाख करोड़ तक घरेलू खरीद का विस्तार यह स्पष्ट करता है कि भारतीय रक्षा उद्योग पर सरकार का भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। डीआरडीओ के लिए 29,100 करोड़ का आवंटन, जिसमें 17,250 करोड़ पूंजीगत अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित हैं, भविष्य की युद्ध तकनीकों की नींव रखता है। यह निवेश अनुसंधान प्रयोगशालाओं को सीधे रणभूमि की आवश्यकताओं से जोड़ने वाला साबित होगा। आत्मनिर्भरता की इस रणनीतिक यात्रा में निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका लगातार अधिक निर्णायक होती जा रही है। रक्षा अनुसंधान बजट का 25% इन क्षेत्रों के लिए खोलना नवाचार, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। ड्रोन स्वार्म, साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियां और स्पेस वारफेयर जैसी क्षमताएं अब भारत की प्राथमिक सामरिक सूची में शामिल हो चुकी हैं। यह बजट भारत को तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि सशक्त निर्माता और संभावित निर्यातक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है।

रक्षा निर्यात में लगातार हो रही वृद्धि इस नीति की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक भरोसेमंद और सक्षम साझेदार के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। राजस्व व्यय के लिए 3.65 लाख करोड़ और पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान यह दर्शाता है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों का कल्याण भी उतनी ही प्राथमिकता में है। ईसीएचएस में 45% की बढ़ोतरी कर 12,100 करोड़ का आवंटन सैनिक परिवारों के प्रति राष्ट्र की स्थायी और सशक्त प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करता है। वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो चीन का निरंतर सीमा दबाव, पाकिस्तान की अस्थिर और आक्रामक रणनीति तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव भारत के समक्ष जटिल और बहुस्तरीय चुनौतियां खड़ी करता है। ऐसे परिवेश में जीडीपी का लगभग 2% रक्षा पर व्यय करना भारत को विश्व के शीर्ष रक्षा व्यय करने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करता है। क्वाड और आई2यू2 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका लगातार सशक्त हो रही है, और यह रक्षा बजट उस भूमिका को आवश्यक सैन्य आधार और विश्वसनीयता प्रदान करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह निर्विवाद संदेश दिया कि शांति की सबसे ठोस और विश्वसनीय गारंटी सशक्त, सजग और सक्षम सेना ही होती है। यह रक्षा बजट उसी सीख को संकल्प से नीति में रूपांतरित करता है। सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन साधते हुए यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को ठोस गति प्रदान करता है। विकसित भारतञ्च2047 के दृष्टिकोण से जुड़ा यह बजट केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नींव रखता है। 7.85 लाख करोड़ का यह रक्षा बजट भारत की नई सामरिक पहचान का स्पष्ट घोषणापत्र है। यह पहचान भय से नहीं, आत्मविश्वास और सामर्थ्य से गढ़ी गई है। स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से एकजुट भारतीय सेनाएं आज राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं। हर रुपये में राष्ट्रभक्ति और हर निर्णय में अडिग संकल्प झलकता है। यह बजट स्पष्ट करता है कि भारत अब केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अपने भविष्य की दिशा स्वयं निर्धारित करता है।

प्रो. आरके जैन

गगनयान से गूंजता भारतअंतरिक्ष में आत्मनिर्भर राष्ट्र का उदय

भारत आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसका आत्मविश्वास आकाश से भी ऊंचा दिखाई देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा गगनयान मिशन की तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल सपने देखने वाला देश नहीं रहा बल्कि उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इससे पहले प्रस्तावित मानवरहित मिशन भारत की वैज्ञानिक सोच अनुशासन और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसरो अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि गगनयान कार्यक्रम की शुरुआत 2027 से होगी और उससे पहले तीन मानवरहित मिशन पूरे किए जाएंगे। यह रणनीति बताती है कि भारत किसी भी सफलता को जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठोस तैयारी और कठोर परीक्षण के बाद ही हासिल करना चाहता है। अंतरिक्ष यात्रा में मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि होती है और भारत इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से समझता है। मानवरहित गगनयान मिशन भारत की पहली प्राथमिकता है क्योंकि यह पूरे कार्यक्रम की नींव है। इसमें प्रयुक्त हर प्रणाली हर तकनीक और हर यंत्र की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। रॉकेट प्रणाली हो या कैप्सूल नियंत्रण तंत्र हो या पुनः प्रवेश प्रणाली हर स्तर पर शत प्रतिशत सफलता का लक्ष्य रखा गया है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की परिपक्वता और वैश्विक मानकों के अनुरूप सोच को दर्शाता है। गगनयान का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में मानव भेजना नहीं है बल्कि यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तीन सदस्यीय दल को तीन दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना अत्यंत जटिल कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार करना ही यह साबित करता है कि भारत अब उन देशों की पंक्ति में खड़ा है जो अंतरिक्ष विज्ञान में नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल अभियान तक भारत ने कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन उपलब्धियों ने यह धारणा तोड़ दी है कि केवल विकसित देश ही अंतरिक्ष में सफलता पा सकते हैं। भारत ने यह सिद्ध किया है कि संकल्प और वैज्ञानिक दृष्टि हो तो सीमित संसाधनों में भी असाधारण परिणाम संभव हैं। गगनयान मिशन उसी निरंतर प्रगति की अगली कड़ी है। यह केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का विषय है। आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है तब अंतरिक्ष में मानव भेजना देश की नई पहचान गढ़ने वाला कदम है। यह युवा पीढ़ी को विज्ञान अनुसंधान और नवाचार की ओर प्रेरित करेगा और देश में वैज्ञानिक सोच को और मजबूत करेगा। दुनिया आज भारत को नए दृष्टिकोण से देख रही है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति तकनीकी क्षमता और कूटनीतिक संतुलन ने उसे वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका में ला खड़ा किया है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता ने इस साख को और मजबूत किया है। यही कारण है कि कुछ विकसित देश भारत की इस तेज प्रगति से असहज महसूस कर रहे हैं। भारत को कमतर आंकने के प्रयास किए जाते हैं लेकिन हर सफल मिशन उन प्रयासों को निष्फल कर देता है। स्वतंत्रता के बाद के भारत और पिछले बारह वर्षों के भारत की तुलना की जाए तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आज भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन अंतरिक्ष तकनीक डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में भारत ने जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। गगनयान मिशन इसी विकास यात्रा का प्रतीक है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक सुविचारित योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को संचार मौसम पूर्वानुमान आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मानव अंतरिक्ष मिशन भारत को अनुसंधान नवाचार और वैश्विक सहयोग के नए अवसर प्रदान करेगा। गगनयान के मानवरहित मिशन यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे तब हर प्रणाली पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो। यह धैर्य और अनुशासन भारत की कार्य संस्कृति को दर्शाता है। भारत दिखावे की नहीं बल्कि स्थायी सफलता की राह पर चलने वाला राष्ट्र है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अंतरिक्ष की सफलताओं ने यह साबित कर दिया है कि भारत किसी से पीछे नहीं है। युवा वैज्ञानिकों की मेहनत अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और राष्ट्रीय नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। भविष्य में गगनयान केवल एक मिशन नहीं रहेगा बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आधार बनेगा। इससे आगे चलकर अंतरिक्ष स्टेशन गहरे अंतरिक्ष मिशन और वैश्विक साझेदारियां संभव होंगी। भारत ज्ञान विज्ञान और मानवता के हित में अंतरिक्ष का उपयोग करने वाला अग्रणी राष्ट्र बनेगा। गगनयान की तैयारी यह संदेश देती है कि भारत सुरक्षित साहसी और दूरदर्शी है। यह राष्ट्र चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। आने वाला समय भारत का है और अंतरिक्ष में गूंजता गगनयान उसी उज्ज्वल भविष्य की उद्घोषणा है।

कांतिलाल मांडोत

'मदर ऑफ ऑल डील्स' को कैसे प्रभावी बनाए सरकार?

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के रूप में जाना जा रहा है, 27 जनवरी, 2026 को संपन्न हुआ है। यह समझौता लगभग दो दशकों की लंबी वार्ताओं का परिणाम है और इसमें 2 अरब से अधिक की आबादी तथा 27 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था शामिल है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा कवर करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। यह समझौता भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करता है, विशेषकर ऐसे समय में जब अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है। हालांकि, इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार को रणनीतिक कदम उठाने होंगे, जिसमें अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार की चेतावनियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ भारत में निर्यात होने वाले 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिससे यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो (लगभग 4.7 बिलियन डॉलर) की बचत होगी। भारत ने यूरोपीय संघ को 102 सेवा उप-क्षेत्रों में पहुंच प्रदान की है, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को 144 उप-क्षेत्रों में अवसर दिए हैं, जिसमें वित्तीय, समुद्री और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र में यूरोपीय कारों पर वर्तमान 110 प्रतिशत टैरिफ को धीरे-धीरे 10 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। भारत के लिए यह समझौता टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देगा। अनुमान है कि यह समझौता 2032 तक यूरोपीय संघ के भारत में निर्यात को दोगुना कर देगा। साथ ही, यह अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जहां भारत के श्रम-गहन निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह समझौता 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया'योजनाओं के साथ तालमेल बैठाता है। यह न केवल निर्यात को बढ़ाएगा बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारतीय एमएसएमई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने का अवसर देगा। हालांकि, इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार की चेतावनियां प्रासंगिक हैं। प्रोफेसर कुमार, जो काले धन और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, ने भारत-यूरोपीय संघ एफटीए को 'अमेरिका जैसा एक और जाल' बताया है। उन्होंने असमान शर्तों, घरेलू उद्योगों विशेषकर कृषि और डेयरी पर जोखिम, व्यापार घाटे में वृद्धि, नीति स्थान की हानि और दीर्घकालिक आर्थिक निर्भरता की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पिछले एफटीए में भागीदारों को अधिक लाभ हुआ है, और निवेश नियमों, नियामक संरेखण तथा बाजार बाढ़ से आत्मनिर्भरता कमजोर हो सकती है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार समझौतों से सबक लेने की सलाह दी है, जहां कृषि बाजार खोलने की मांग भारत के लिए कठिन है।

इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को रचनात्मक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। समझौते में डेयरी और कुछ कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है, लेकिन कुमार की चेतावनी के अनुसार, बाजार बाढ़ से बचने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करें। सरकार कृषि क्षेत्र में सब्सिडी और समर्थन को मजबूत करे, जैसे कि फसल बीमा और बाजार लिंकेज को बढ़ावा देकर। साथ ही, एग्रीस्टैक जैसी डिजिटल पहलों को तेज करें ताकि किसान वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें।

दूसरा, एमएसएमई और छोटे उद्योगों की तैयारी पर फोकस करें। प्रोफ़ेसर कुमार की निर्भरता की चेतावनी को संबोधित करने के लिए, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम को विस्तार दें, विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में। एमएसएमई को क्रेडिट पहुंच, कौशल विकास और निर्यात प्रशिक्षण प्रदान करें। यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त निवेश कोष स्थापित करें जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित हो, ताकि 'मेक इन इंडिया' मजबूत हो सके।

तीसरा, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी मानकों का अनुपालन। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम), जो 1 जनवरी, 2026 से पूर्ण रूप से लागू है, भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर कार्बन टैक्स लगा सकता है, जिससे निर्यातकों को 22 प्रतिशत तक कीमत कम करनी पड़ सकती है। सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाकर, जैसे कि 500 जीडब्ल्यू सौर लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़कर, इस चुनौती का सामना करना चाहिए। सीबीएएम-अनुपालन प्रमाणन प्रणाली विकसित करें और यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शुरू करें।

चौथा, व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए विविधीकरण। प्रोफ़ेसर कुमार की व्यापार घाटे की चेतावनी को देखते हुए, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए बाजारों की तलाश करें, जैसे कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। साथ ही, समझौते के तहत निवेश नियमों को मजबूत करें ताकि नीति स्थान सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय निवेश बोर्ड को सक्रिय करें जो विदेशी निवेश की समीक्षा करें और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें। पांचवां, मानव संसाधन और प्रवासन पर फोकस। समझौता प्रवासन और मोबिलिटी फ्रेमवर्क से जुड़ा है, जो 'टैलेंट एंड सिक्योरिटी' पर केंद्रित है। सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए, जैसे कि आईटी और इंजीनियरिंग में। इससे युवा रोजगार बढ़ेगा और ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकेगा। इन सुझावों से, सरकार यदि चाहे तो प्रोफ़ेसर कुमार की चेतावनियों को अवसर में बदल सकती है। समझौता वैश्विक अनिश्चितताओं, जैसे कि अमेरिकी टैरिफ और चीन से व्यापार विचलन के बीच, भारत को रणनीतिक लाभ देगा। अनुमान है कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 41-65 प्रतिशत बढ़ाएगा और जीडीपी में 0.12-0.13 प्रतिशत की वृद्धि करेगा। यह चीन से व्यापार विचलन (5-9 प्रतिशत) को बढ़ावा देगा, जो यूरोपीय संघ की डी-रिस्किंग और भारत की विविधीकरण रणनीति से मेल खाता है। 'मदर ऑफ ऑल डील्स' भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जाने का माध्यम बन सकता है। कबीरदास के दोहे, 'निंदक नियरे राखिए, ऑंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करें सुभाय।।' को ध्यान में रखते हुए सरकार को प्रोफेसर कुमार की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए और संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना साकार करने के लिए यह समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्तेइसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

संपादकीय

संसद का बजट सत्र और लोकतांत्रिक विमर्श की कसौटी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से उभरते सत्ता-विपक्ष के तर्क

संसद के बजट सत्र का चौथा दिन भारतीय लोकतंत्र के उस जीवंत पक्ष को सामने लाता है, जहां सरकार और विपक्ष एक ही मंच पर देश की दिशा, प्राथमिकताओं और नीतिगत दावों पर खुली बहस करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा इसी परंपरा का केंद्रीय पड़ाव है। यह केवल औपचारिक धन्यवाद नहीं, बल्कि सरकार के पूरे एजेंडे पर संसद की सामूहिक प्रतिक्रिया होती है। लोकसभा में सांसद सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के साथ शुरू हुई यह बहस 18 घंटे तक चलेगी, जिसमें सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करेगा तो विपक्ष अपने सवालों और आपत्तियों के साथ सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा। इसी बहस के बीच प्रधानमंत्री का 4 फरवरी को जवाब और वित्त मंत्री का 11 फरवरी को बजट से जुड़े प्रश्नों पर उत्तर, सत्र की दिशा तय करेंगे।

इस वर्ष का बजट सत्र दो चरणों में विभाजित है, जो संसदीय कामकाज की व्यापकता और गंभीरता को रेखांकित करता है। पहले चरण में राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट प्रस्तुत हुआ, जबकि दूसरे चरण में मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा, वोटिंग और वित्तीय विधेयकों का पारित होना तय है। यह संरचना बताती है कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नीतियों, प्राथमिकताओं और राजनीतिक संकल्पों का समुच्चय है, जिसे संसद की कसौटी पर परखा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच वैचारिक टकराव स्वाभाविक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता इस बहस में भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत एक आत्मीय धन्यवाद के साथ की और तत्काल एक प्रतीकात्मक संदर्भ चुना पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की आत्मकथा। यह चयन अपने आप में संदेश देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति और संस्थागत दृष्टिकोण जैसे विषय विपक्ष के विमर्श के केंद्र में हैं। हालांकि, उनके वक्तव्य के दौरान हंगामा भी हुआ, जो संसद की उस वास्तविकता को दर्शाता है जहां तीखे आरोप-प्रत्यारोप अक्सर संवाद को बाधित कर देते हैं।

विपक्ष की रणनीति स्पष्ट दिखती है। एक ओर वह बजट की सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है, दूसरी ओर सरकार के नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख कर कांग्रेस यह बताने की कोशिश कर रही है कि पूर्ववर्ती नीतियों ने ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई थी, जबकि नई योजनाओं में खामियां हैं। केरल के सांसदों का प्रदर्शन और राज्य के प्रति उपेक्षा के आरोप संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संबंधों की पुरानी बहस को फिर से सामने लाते हैं। विपक्ष के लिए यह मंच न केवल आलोचना का, बल्कि अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण को रखने का अवसर भी है।

सत्ता पक्ष का रुख भी उतना ही आक्रामक और आत्मविश्वासी है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का लंबा वक्तव्य सरकार की वैचारिक दिशा और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कांग्रेस के पिछले दस वर्षों के भाषणों में संस्कृति, स्टार्ट-अप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विकसित भारत जैसे शब्दों की अनुपस्थिति का उल्लेख कर यह तर्क दिया कि देश की आकांक्षाएं बदली हैं और वर्तमान सरकार ने उन आकांक्षाओं को शब्द और दिशा दी है। यूपीआई, आईपीओ और डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि युवाओं की शब्दावली और सपने कैसे बदले हैं। यह बहस केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों की है।एक ओर परंपरागत कल्याणकारी राज्य का मॉडल, दूसरी ओर विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर।

तेजस्वी सूर्या का सांस्कृतिक विमर्श भी उल्लेखनीय है। मंदिरों के विकास, राम मंदिर के उद्घाटन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की बात करते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि सरकार केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी अपनी उपलब्धि मानती है। इसके साथ ही कांग्रेस की चुनावी पराजयों का उल्लेख कर राजनीतिक बढ़त का दावा किया गया। ऐसे वक्तव्य संसद को एक ऐसे मंच में बदल देते हैं जहां नीतिगत चर्चा के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी जनता तक पहुंचाया जाता है।

राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी व्यापक तस्वीर का हिस्सा है। धन्यवाद प्रस्ताव का पेश होना, प्रश्नकाल में न्यायिक भर्ती के लिए राष्ट्रीय प्रणाली की मांग, जयललिता को भारत रत्न देने की मांग जैसे मुद्दे यह दिखाते हैं कि संसद केवल बजट तक सीमित नहीं, बल्कि विविध राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सवालों का केंद्र है। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर की यह टिप्पणी कि सवाल और जवाब संक्षिप्त होने चाहिए, संसदीय दक्षता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करती है। इस पूरे सत्र की पृष्ठभूमि में 1 फरवरी को प्रस्तुत आम बजट की छाया स्पष्ट दिखती है। 85 मिनट का बजट भाषण सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का खाका था, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अब धन्यवाद प्रस्ताव की बहस उस खाके और रिपोर्ट कार्ड की राजनीतिक समीक्षा है। विपक्ष जहां सामाजिक न्याय, रोजगार और संघीय संतुलन पर जोर दे रहा है, वहीं सरकार बुनियादी ढांचे, नवाचार, वैश्विक भूमिका और सांस्कृतिक पहचान को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बजट सत्र लंबा और चरणबद्ध है। पहले चरण के बाद अवकाश और फिर दूसरे चरण में अनुदान मांगों पर चर्चा, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय प्रस्तावों की गहन जांच हो सके। मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांट की चर्चा और वोटिंग लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल तत्व है, क्योंकि यहीं सरकार को यह स्पष्ट करना होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे और क्यों किया जाएगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे विवाद, आरोप और हंगामे संसद की सीमाओं को भी उजागर करते हैं। संवाद की जगह शोर, और तर्क की जगह नारे जब हावी हो जाते हैं, तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ता है। फिर भी, यही बहसें लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण भी हैं। विभिन्न विचारों का टकराव, असहमति का खुला प्रदर्शन और अंततः प्रधानमंत्री का जवाब यह सब मिलकर संसदीय प्रक्रिया को पूर्णता देता है।

प्रधानमंत्री का 4 फरवरी को प्रस्ताव पर उत्तर इस सत्र का निर्णायक क्षण होगा। परंपरागत रूप से यह उत्तर न केवल विपक्ष के सवालों का जवाब होता है, बल्कि सरकार की भविष्य की दिशा का संकेत भी देता है। इसी तरह वित्त मंत्री का बजट पर उत्तर वित्तीय बहस को समेटने का काम करेगा। इन दोनों जवाबों से यह स्पष्ट होगा कि सरकार आलोचनाओं को कैसे देखती है और किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

कुल मिलाकर, संसद का बजट सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा भारतीय लोकतंत्र का वह आईना है, जिसमें देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बहसें एक साथ प्रतिबिंबित होती हैं। यहां केवल कानून और बजट नहीं बनते, बल्कि विचार गढ़े जाते हैं, दावे परखे जाते हैं और जनता के सामने सत्ता का लेखा-जोखा रखा जाता है। यही कारण है कि इस सत्र की कार्यवाही केवल संसदीय रिकॉर्ड नहीं, बल्कि समकालीन भारत की कहानी भी है।एक ऐसी कहानी जिसमें विकास की आकांक्षा, सामाजिक न्याय की मांग, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सभी एक साथ चलती हैं।

आतंकियों को पालोगे तो आत्मसम्मान ही नहीं, देश भी गिरवी रखना पड़ेगा

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में उद्योगपतियों के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा दिया गया बयान कि पाकिस्तान को विदेशों से कर्ज मांगते समय अपना आत्मसम्मान तक गिरवी रखना पड़ता है—दरअसल कोई नई बात नहीं है। यह स्वीकारोक्ति पाकिस्तान की उस भयावह आर्थिक और राजनीतिक सच्चाई को उजागर करती है, जिसमें वह वर्षों से फंसा हुआ है । खनिज संपदाओं और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध, मेहनतकश पठानों का देश पाकिस्तान आज जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसके लिए बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि उसकी अपनी नीतियां जिम्मेदार हैं। भारत के प्रति जन्मजात नफरत और उसके अस्तित्व को मिटाने की सनक में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आतंकवाद को राज्य-नीति बना लिया। नतीजा यह हुआ कि देश कर्ज के दलदल में इस कदर धंस गया कि अब उसके कई हिस्से और उद्योग चीन के पास गिरवी रखे जा चुके हैं। आज पाकिस्तान के अनेक रणनीतिक ठिकानों पर चीन का प्रत्यक्ष प्रभाव किसी से छिपा नहीं है।

भारत के प्रति पाकिस्तान की दुश्मनी कोई आज की बात नहीं है। बंटवारे के समय से ही भारत यह सब देखता आ रहा है पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का कत्लेआम, बहन-बेटियों के साथ की गई बर्बरता और नफरत की वह आग, जो आज भी बुझने का नाम नहीं ले रही। हर युद्ध, हर साजिश और हर आतंकवादी प्रयास में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उसकी नफरत कम नहीं हुई । कट्टरपंथी ताकतों ने इस्लाम और अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान की गरीबी का फायदा उठाया। मासूम युवाओं को बहलाकर उनके हाथों में बंदूकें थमाई गई और भारत में आतंक फैलाने भेजा गया। दशकों तक पाकिस्तान इस नीति में लगा रहा और आज भी उसकी दहशतगर्दी की कोशिशें जारी हैं। आतंकवादी शिविर, प्रशिक्षण केंद्र और उनके रख-रखाव पर होने वाला भारी खर्च—सब कुछ पाकिस्तानी सरकार की शह पर चलता रहा।

यदि यही धन पाकिस्तान ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया होता, तो आज वह विकास के मामले में कई देशों से आगे होता। लेकिन जिस देश का जन्म ही नफरत की बुनियाद पर हुआ हो, उससे भारत के साथ भाईचारे की उम्मीद करना बेमानी है । पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां जो भी शासक भारत के साथ बेहतर संबंधों और जनता की भलाई की बात करता है, उसे सेना और कट्टरपंथी ताकतें बर्दाश्त नहीं करतीं। कई लोकप्रिय हुक्मरानों को तख्तापलट कर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। वहां की सेना ने कभी लोकतांत्रिक सरकारों को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया, यही कारण है कि पाकिस्तान आज भी निर्णायक नेतृत्व से वंचित है । प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दर्द दरअसल हर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का दर्द रहा है। आत्मसम्मान गिरवी रखकर कर्ज मांगने की यह मजबूरी उन्हीं नीतियों का परिणाम है, जिनमें सत्ता के लिए सेना और कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए गए।

जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सफाया नहीं करता, आतंकी संगठनों को संरक्षण और आर्थिक मदद देना बंद नहीं करता, तब तक उसके हुक्मरान यूं ही आत्मसम्मान गिरवी रखकर दुनिया के दरवाजे खटखटाते रहेंगे। जिस दिन पाकिस्तान की जनता और युवा कट्टरपंथ और सैन्य वर्चस्व के खिलाफ खड़े होकर देशहित में काम करने वाली लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, उसी दिन पाकिस्तान को यह अपमान झेलना नहीं पड़ेगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जब आत्मसम्मान के साथ-साथ पूरा पाकिस्तान ही गिरवी रखा हुआ दिखाई देगा।

अरविंद रावल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप

ग्रामीणों के विरोध पर लौटाए रुपये, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे कालिका बख्श का पुरवा मजरे ऐहार गांव में सोमवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि निजी कंपनी के दो कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर बदलने के नाम पर ग्रामीणों से एक-एक हजार रुपये ले लिए। ग्रामीणों के विरोध के बाद कर्मचारियों ने रुपये वापस कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को निजी कंपनी के दो कर्मचारी गांव पहुंचे थे। उन्होंने पुराने मीटर में गड़बड़ी बताकर स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने कई ग्रामीणों से एक हजार रुपये की मांग की। कुछ लोगों से रुपये भी ले लिए गए। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कारण पूछा तो कर्मचारियों ने बिजली चोरी का मामला दर्ज कराने की धमकी देने की बात कही। इससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। दबाव बढ़ने पर कर्मचारियों ने ली गई रकम वापस कर दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि स्वतंत्र प्रभात इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गांव निवासी संतोष कुमार, पप्पू, पिंटू साहू और बाबू ने बताया कि स्मार्ट मीटर कर्मचारियों ने उनसे रुपये लिए थे। बाद में हंगामा होने पर पैसे लौटा दिए गए। इस संबंध में एसडीओ शिवम वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती, भंडारे में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के कालिकाबख्श का पुरवा मजरे ऐहार गांव में महान संत भगवान रविदास की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने केक काटकर भगवान रविदास व डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। गांव के अंबेडकर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गांववासियों ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी ने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज को समानता, भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। साथ ही संत रविदास के प्रसिद्ध कथन 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कविताओं और गीतों के माध्यम से संत रविदास की स्तुति प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस मौके पर मोहम्मद नसरुद्दीन रंजीत, आशीष, सोनू, रामनारायण, शीलू साहू, रमेश, धानू, विनोद यादव, हरिमोहन, विजय, सुमन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे।

फ़ोटो0021

42वां श्री विष्णु महायज्ञ व संगीतमय राम कथा महोत्सव भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ

बिसवां सीतापुर श्री राम चरित मानस समिति के तत्वावधान में 42 वां श्री विष्णु महायज्ञ व संगीतमय रामकथा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। मानस मंदिर स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जो बाबा मंशाराम मंदिर, प्राचीन हनुमानजी मंदिर, पत्थर शिवाला मंदिर होते हुए पुरैनी नहर में पहुचकर कलश में पानी भरकर यात्रा का समापन मानस मंदिर पर हुआ। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर पीले वस्त्र धारण करके चल रही थी।कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए वैद्य रामकिशोर शुक्ला, अवधेश शुक्ला, रामनाथ शुक्ला, पुनीत शुक्ला, अंशू, सानुज शुक्ला व बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा।कार्यक्रम आयोजक वैद्य रामकिशोर शुक्ला ने बताया कि आयोजन 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। जिसमे प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक व शाम को 7 से 10 बजे तक संगीतमय रामकथा कथाव्यास आचार्य दीपक शुक्ला जी महाराज के द्वारा भक्तो को रसपान करवाया जायेगा। यज्ञ के मुख्य यजमान अजय रस्तोगी व कथा यजमान राकेश रस्तोगी है। उन्होंने सभी भक्तों से आयोजन को सफल बनाने की अपील की।

रात के अंधेरे में कटे सात सरकारी पेड़ सबूत मिटाने के लिए जेसीबी से खोदे गड्ढे, ग्रामीणों ने की शिकायत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में सरकारी पेड़ों की अवैध कटान का गंभीर मामला सामने आया है। चौकी चांदपुर अंतर्गत कटरा गांव के पास सड़क किनारे खड़े बहुमूल्य सरकारी पेड़ों को रात के अंधेरे में काटे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं और लकड़ी ठेकेदारों ने मिलकर यह अवैध कटान किया है स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में भिलोर और सिरसा प्रजाति के कुल सात सरकारी पेड़ों को काट दिया गया कटे हुए पेड़ों की लकड़ी ट्राले में भरकर मौके से फरार हो गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के उद्देश्य से जेसीबी मशीन की मदद से कटे हुए पेड़ों के ठूंठों को मिट्टी से ढक दिया गया, ताकि घटना के निशान न मिल सकें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस अवैध कटान में मुन्ना ठेकेदार निवासी रामद्वारी, खनन माफिया नरेंद्र वर्मा, अंकित वर्मा और अर्जुन सिंह के नाम सामने आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि जब वन विभाग के कर्मचारी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, तो कथित रूप से उनका पीछा किया गया और दबाव बनाने का प्रयास किया गया आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने एक भाजपा नेता का नाम लेकर राजनीतिक संरक्षण की बात भी कही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद बिना कोई ठोस कार्रवाई किए वापस लौट गई इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कटान का मामले सामने आने के बाद क्षेत्र में अवैध कटान और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होने की चर्चा तेज हो गई है ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है फिलहाल वन विभाग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, और लोग जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं!!

वन विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से फलफूल रहा है अवैध लकड़ी कटान का व्यापार

- उप प्रभागीय वन निदेशक बिसवां(एसडीओ) ब्रजेश पाण्डेय वनक्षेत्राधिकारी हरगांव बीनू पाल और केसरीगंज चौकी प्रभारी मनोज गुप्ता की भूमिका सवालों के घेरे में
- प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों के कटान की लगातार घट रहीं हैं घटनायें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर सीतापुर जनपद की लहरपुर तहसील के वन क्षेत्र हरगांव में स्थानीय पुलिस और वन कर्मियों की मिली भगत से प्रतिबंधित प्रजाति के हरे पेड़ों का अवैध कटान लगातार हो रहा है और लगातार घट रही घटनाओं के बावजूद उच्च अधिकारियों की चुप्पी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीती 30-31 जनवरी की रात क्षेत्र के ग्राम नबीनगर के मजरा फत्तेपुर मे प्रशासनिक मिलीभगत से मनबढ़ लकड़कट्टों ने एक नीम और सात आम के पेड़ों पर आरा चला डाला। लेकिन मीडिया के संज्ञान मे आ जाने से पहले तो दोपहर

तक मैनेजमेंट का खेल चलता रहा पर आखिरकार दोपहर बाद वनकर्मियों की तहरीर पर स्थानीय कोतवाली लहरपुर मे उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों मे वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 3 व 7 और उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एण्ड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स 1978 की धारा 3 व 28 के तहत मु0अ0सं0 0037/2026 दर्ज करा दिया गया। सूत्रों की माने तो ये अवैध तरीके से कटान का सिलसिला स्थानीय वन व पुलिस कर्मियों की सांठगांठ से लगातार चलता रहता है और इक्का-दुक्का मामले ही मीडिया की नजरों तक पहुंचते हैं जिनमे पेंड़ मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

केंद्रीय बजट दिशाहीन और जनविरोधी: संजीव

देवरिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने निराशाजनक और जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं देता, बल्कि केवल पूंजीपतियों के हितों को साधने वाला है। संजीव मिश्रा ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठोस रोडमैप नहीं है, वहीं किसानों के लिए भी पर्याप्त उपायों का अभाव है। महंगाई पर नियंत्रण को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दरों में कोई बदलाव न होने से मध्यम वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। यह बजट केवल सपने दिखाने वाला है, वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करता।

तेज़ रफ़्तार एर्टिगा ने बाइक को मारी टक्कर भतीजे की मौत चाचा सहित दो घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं खैराबाद थाना क्षेत्र के कैथाभारी के पास तेज रफ्तार एर्टिगा कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई मृतक युवक की पहचान ग्राम निजामाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है। वह अपने चाचा देशराज और साथी लक्ष्मीनारायण के साथ होटल में कैटरिंग का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था रात का वक्त होने के चलते सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही बाइक कैथाभारी के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार एर्टिगा कार ने सीधी टक्कर मार दी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे। बाइक चला रहे अंकित को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया वहीं देशराज और लक्ष्मीनारायण लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े रहे। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर खैराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में शामिल एर्टिगा कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है अंकित की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई। घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल कार को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलते ही मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार चालक की तलाश जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरनाक नतीजों की याद दिला दी है!!

सही मार्गदर्शन से प्रतिभाओं में आता है निखार: प्रेमनाथ

- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान बच्चों को अविरल फाउंडेशन ने किया सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लंभुआ। सुल्तानपुर शिक्षक एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन से प्रतिभाओं में निखार आता है। इसलिए बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उनमें सकारात्मक सोच पैदा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उक्त विचार सम्मान समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विद्यालय प्रबंधक प्रेमनाथ शुक्ला ने व्यक्त किए।

लंभुआ में अविरल फाउंडेशन की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष भानुकर तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के कई विद्यालयों के बच्चे फाउंडेशन द्वारा कराए गए सामान्य

ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। दिसंबर माह में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परीक्षाफल घोषित किया गया था। जिसमें बच्चों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जूनियर स्तर प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर अर्जुनपुर के अयांश सरोज को प्रथम स्थान, नेशनल एकेडमी करनपुर के सूर्यांश सिंह बघेल द्वितीय स्थान तथा साक्षी यादव को तृतीय स्थान मिलने पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोपालपुर मधैया के प्रबंधक प्रेमनाथ शुक्ला ने बच्चों को सम्मानित किया। प्राथमिक स्तर पर प्रथम स्थान गांधी शिक्षण संस्थान की खुशनूर, द्वितीय स्थान पंडित नागेश्वर बाल विद्या मंदिर के अभिनव यादव तथा दिव्या दीक्षा शिक्षण संस्थान की आस्था प्रजापति को तृतीय स्थान प्राप्त होने पर उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर चंदन चतुर्वेदी, रंजीत सिंह, दीपक पांडे, प्रवीण पाठक, गणेश पांडे, राजीव मिश्रा, सुशील कुमार यादव, रमेश पांडे, मंगल विश्वकर्मा, सूरज यादव आदि मौजूद थे।

भैस चोरी के आरोप में तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा

क्राइम

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव में हुई भैंस चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरी की गई दोनों भैंस भी बरामद कर ली हैं। रविवार की रात गांव निवासी शिवमोहन विश्वकर्मा की दो भैंस घर के दरवाजे पर बंधी थीं। रात में अज्ञात लोगों ने दोनों भैंस खोलकर चोरी कर ली। सुबह पशुपालक को घटना की जानकारी हुई। उसने तुरंत कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। शिकायत में बताया गया कि गांव का ही मोनू उर्फ राजकुमार यादव अपने दो साथियों के साथ भैंस चोरी में शामिल था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंगलवार को पुलिस ने मोनू उर्फ राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया। उसके साथ खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज रायखेड़ा गांव निवासी दीपू और उसके पिता सल्लर को भी पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई दोनों भैंस बरामद कर लीं। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

वैश्विक शोध जगत में भारतीय अकादमिक की सशक्त उपस्थिति: उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रो. भरत राज सिंह को एल्सेवियर जर्नल्स का औपचारिक सम्मान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रकाशन संस्था एल्सेवियर जर्नल्स ने वर्ष 2025 के दौरान वैश्विक शोध समुदाय को सुदृढ़ बनाने में किए गए उल्लेखनीय पीयर-रिव्यू योगदान के लिए *वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं शोधकर्ता प्रो. भरत राज सिंह, महानिदेशक स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ के प्रति औपचारिक आभार व्यक्त किया है। एल्सेवियर जर्नल्स लीडरशिप टीम द्वारा भेजे गए प्रशस्ति-पत्र में कहा गया है कि प्रो. भरत राज सिंह द्वारा प्रदत्त समय, गहन अकादमिक विवेक और विशेषज्ञ मूल्यांकन ने प्रकाशित शोध की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिक दिशा को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि पीयर-रिव्यू सुदृढ़, नैतिक और प्रभावी शोध की आधारशिला है। प्रो. सिंह जैसे समर्पित समीक्षकों की अंतर्दृष्टि और बौद्धिक प्रतिबद्धता ही शोध समुदाय को आगे बढ़ाती है और नवाचार को विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। यद्यपि यह कार्य प्रायः पर्दे के पीछे संपन्न होता है, किंतु इसका प्रभाव दूरगामी और स्थायी होता है। एल्सेवियर जर्नल्स की प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) लॉरा हैसिंक ने अपने संदेश में कहा कि 'प्रो. भरत राज सिंह का योगदान यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाशित शोध कठोर अकादमिक मानकों पर खरा उतरे और जिन समुदायों की यह सेवा करता है, उनके लिए वास्तविक रूप से मूल्यवान सिद्ध हो।' एल्सेवियर ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 की ओर बढ़ते हुए संस्था पीयर-रिव्यू अनुभव को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और समीक्षक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत स्पष्ट मार्गदर्शन, अधिक प्रासंगिक आमंत्रण तथा समीक्षकों के योगदान को औपचारिक मान्यता देने की पहल को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रो. भरत राज सिंह का यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया योगदान न केवल भारतीय अकादमिक जगत के लिए गौरव का विषय है, बल्कि यह युवा शोधकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा है कि अकादमिक ईमानदारी, बौद्धिक निष्पक्षता और समर्पण से ही ज्ञान की प्रगति संभव है।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की सुनी समस्याएं, दिये निस्तारण के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली: जनपद रायबरेली के सामुदायिक केन्द्र, रतापुर में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश प्रो0 हिमांशु शेखर झा ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित मोबाइल कोर्ट का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। मोबाइल कोर्ट में अपनी समस्याओं के साथ आए दिव्यांगजनों की समस्याओं पर राज्य आयुक्त द्वारा सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांगता प्रमाणन (मेडिकल बोर्ड), यूडीआईडी, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, रेल कन्सेशन प्रमाण-पत्र आदि के स्टॉल लगाए गए। शिविर में उपस्थित दिव्यांगजनों की कुल 182 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

मोबाइल कोर्ट में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, नगर निकाय, विद्युत विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे साथ ही संबंधित बैंकों के अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा भी उपस्थित रहे।

दिव्यांगता प्रमाणन हेतु चिकित्सकीय बोर्ड की उपस्थिति सुनिश्चित की गई तथा आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की मूल भावना के अनुरूप विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लखनऊ मंडल राजेश मिश्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सृष्टि अवस्थी, जिला पिछड़ा वर्ग कलयाण अधिकारी मोहन त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्यशील सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उबेर्दुरहमान सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सर्राफा व्यापारी से लूट मामला सीसीटीवी में दिखे बदमाश, पुलिस ने 3 KM तक खंगाले फुटेज, दस टीमें जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के सकरन थाना इलाके में बीती 2 दिन पूर्व सर्राफा व्यापारी से हुई लूटपाट मामले में पुलिस को सीसीटीवी से अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने घटना से कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार दो बदमाशों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में सर्विलांस टीम के साथ अन्य साक्ष्यों को भी जुटने में लगी हुई है। वही वारदात के बाद सर्राफा व्यापारियों में भी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए है मालूम हो कि शनिवार की देर शाम बिसवा कोतवाली इलाके के रहने वाले सर्राफा व्यापारी मोनू रस्तोगी सकरन इलाके में अपनी दुकान बंद करते हुए वापस अपने घर

की तरफ आ रहे थे। आरोप है इस दौरान रास्ते में बाइक सवार दो नकाब पोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनके पास मौजूद 2 लाख कीमत जेवरों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए इस वारदात के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल समेत भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की थी। घटना के दूसरे दिन रविवार को पुलिस टीम ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस जुड़ते हुए वारदात की जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर तक करीब 12 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। वहीं पुलिस को इस घटना के खुलासे के लिए करीब 10 टीमों को लगाया गया है जो मामले में छानबीन कर घटना के अनावरण में लगी हुई है सकरन पुलिस ने इस मामले में पीड़ित सर्राफा व्यापारी की तहरीर पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के प्रयास किए जा रहे है!!

कार्यालय ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर विकास खण्ड लम्भुआ सुल्तानपुर

पत्रांक.मेमो/मनरेगा/ग्रा0पं0निविदा-2025.26 दिनांक. 21/01/2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर मे मनरेगा राज्यवित्त चौदहवां वित्त योजनान्तर्गत निम्न निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत के उपरांत निम्न कार्य एवं कार्यस्थल पर निम्न विवरण के अनुसार स्थानीय भट्ठा मालिकध्रजिस्टर्ड ठेकेदार एवं अन्य सामाग्री आपूर्ति कर्ता जो इच्छुक हो स्वीकृत दर से कम दर पर कार्य कराये जाने हेतु अपना निविदा ग्राम पंचायत मे दिनांक 21/01/2026 से दिनांक 27/01/2026 समय 12 बजे मध्यान्ह तक ग्राम पंचायत मुख्यलाय प्रधानध्सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 27/01/2026 को प्राप्त निविदा ग्राम पंचायत द्वारा गठित समिति के समक्ष अपरान्ह 4:00 बजे खोली जाएगी।

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	कयामुद्दीनपुर	इंटरलाकिंग से जय प्रकाश सिंह के घर से हरिजन बस्ती तकए बाबूलाल पाल के घर तकए इन्द्रेश शर्मा के घर तकए अनिल दूबे एवं धनञ्जय सिंह आदि के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	2,73,000,00	2%	200.00	2 माह
2	कयामुद्दीनपुर	इंटर लाकिंग से अनरुद्ध सिंहए गुलशेर के घर तकए गयासुद्दीन के घर तकए राशिद के घर तकए हरिंदे के घर तकए जल्ले आदि के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	3,25,000,00	2%	200.00	2 माह

नोट- नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस मे देखी व पढ़ी जा सकती हैं।

ग्राम प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत कयामुद्दीनपुर,
विकास खण्ड. लम्भुआ,
सुल्तानपुर

संक्षिप्त खबरें

यूपी के मदरसा में हाफिज ए कुरान के सर पगड़ी बांध कर किया सम्मानित

नई दिल्ली, दारुल वोलूम रिजवीया मदरसा गुमती नगर स्थित जलसा ए दस्तार बंदी का आयोजन किया गया। मौलाना सदारत में हुए इस जलसे में 84 हुफ्फज ए कराम को पगड़ी बांध कर सम्मानित किया गया। बतौर मुखय अतिथि हज़रत मौलाना ने कुरान की शिक्षाओं का महत्व आध्यात्मिक विकास नैतिक आचरण और समाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कुरान न केवल एक धार्मिक मार्गदर्शन है बल्कि यह शिक्षा और ज्ञान को भी अत्यधिक महत्व देता है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जलसा में शामिल होने वाले का गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। इस दस्तार बंदी में विभिन्न प्रदेश से इए तलवा कारी अब्दुल राजीक, मधुबनी। कारी मो उस्मान क़ादरी, सितामढी।कारी मो अली असगर, पुरेनिया। कारी सहबाज आलम, बिहार।कारी मो जमील हुसैन,कारी एहतराम सहीत अन्य तालिबे इल्म को पगड़ी बांध कर दीनी तालीम का प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर डॉ किताबुदिन,मो हाफिज,मो शकील सहित कारी हाफिज एवं अन्य तालिब उपस्थित थे।

दिल्ली के तुगलकाबाद में मामूली विवाद बना जानलेवा, युवक को डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट; जांच जारी

दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में सोमवार को मामूली विवाद के बाद एक युवक हिमांशु कुमार चौहान की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

दक्षिणी दिल्ली। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित तुगलकाबाद गांव में सोमवार को मामूली विवाद के बाद हुए झगड़े में एक युवक की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। हत्या की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपित एक दूसरे को पहले से जानते थे। आरोपितों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतक हिमांशु कुमार चौहान उर्फ अंशु अपने परिवार के साथ कांगड़ मोहल्ला, तुगलकाबाद गांव में रहता था।

यूपी का रहने वाला है परिवार

परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है। हिमांशु कुमार ओखला फेज-1 स्थित एक इंस्टॉलेशन में हाउस कीपिंग का काम करता था, पर पिछले तीन महीनों से वह बेरोजगार था।

उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3:45 बजे पुलिस को झगड़े की सूचना मिली। गोविंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को कंगाड़ मोहल्ला स्थित मकान नम्बर 268 के कमरे के दरवाजे पर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में युवक के पास मिले दस्तावेज और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद मृतक की पहचान कर उसके परिजनों को वारदात की जानकारी दी गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपितों की गिरफ़्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

विश्व आर्द्र भूमि जागरुकता दिवस में वनकर्मियो ने बच्चों को दिखाया छक्षियो की प्रजाति

हलिया, मीरजापुर। स्थानीय वन क्षेत्र के ददरी बाध में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तहत रविवार को वनकर्मियो ने ददरी बाध में बच्चों व ग्रामीणों को पक्षियों की प्रजाति की पहचान कराते हुए गणना किया है जिसमें बाध में काला बगुला व सफेद बगुला की संख्या 20, चकहा 30, पनडुब्बी 10, सिलही 12, नकवा 9, कव्वाल 6, सिलही 3 आदि की गणना करते हुआ पहचान कराया। इस दौरान वन दरोगा सूरज पांडेय, शनी सिंह, नीतू शर्मा, राजकुमार वर्मा, रामदास आदिवासी, शीतला बक्श सिंह, संदीप कुमार, अंकुर शुक्ला, शिवम सिंह आदि के साथ सुरक्षा श्रमिक व ग्रामीण,बच्चे मौजूद रहे।

अमेरिका के हमले का जरा भी खौफ नहीं, खुमैनी के मकबरे से दहाड़े खामनेई

खामनेई ने कोम में जमकरान मस्जिद का दौरा किया। यह स्थल शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उनकी उपस्थिति ने उनके समर्थकों में विश्वास जगाया है। उन्होंने तेहरान में इमाम खुमेनी के स्मारक का दौरा किया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ईरान के सुप्रीम लीडर आया सैयद अली खामिनी कहीं छुपे नहीं है बल्कि वह कुछ दिनों के बाद खुलकर सामने आए हैं और ना सिर्फ सामने आए बल्कि उनकी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों का करारा जवाब दिया है जिसमें उनके छिपे होने या फिर बंकर में जाने की खबरें फैलाई जा रही थी। दरअसल खामनेई ने कोम में जमकरान मस्जिद का दौरा किया। यह स्थल शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उनकी उपस्थिति ने उनके समर्थकों में विश्वास जगाया है। उन्होंने तेहरान में इमाम खुमेनी के स्मारक का दौरा किया। यह दौरा दहा-ए फज्र यानी इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ की शुरुआत के अवसर पर किया गया। उनकी तस्वीरों के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वे देश की कमान पूरी मजबूती के साथ अभी भी संभाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गरजते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है।

ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय आयातुल्लाह अली खामिनी की ये टिप्पणियां अब तक की उनके सबसे प्रत्यक्ष धमकी है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने कामी के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हमें उकसाया नहीं जाना चाहिए और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या फिर उसे परेशान करेगा।

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान यूरोपीय संघ द्वारा ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के फैसले के बाद आया है। यूरोपीय संघ ने यह कदम ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से की गई खूनी कार्रवाई के मद्देनजर उठाया था। कालिबाफ की इस घोषणा को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है। 2019 में पारित एक कानून के तहत ईरान ने अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को भी इसी कैटिगरी में रखा था।

श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के भेटारबंद और सिंगलाछड़ा ज़िप में विकास की लहर

● एक दिन में 7 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से चार परियोजनाओं का शिलान्यास विधायक विजय मालाकार द्वारा।

विधायक ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समय में असम सहित रामकृष्णनगर क्षेत्र के हर कोने में विकास कार्य चल रहे हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः 26वीं विधानसभा चुनाव के दिन के नज़दीक आते ही राज्य भर में विकास कार्य जारी हैं, रामकृष्णनगर क्षेत्र भी पीछे नहीं है। 2 फरवरी (सोमवार) को रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दुल्लभछड़ा के पास स्थित भेटारबंद ज़िप के धूपनपुर ट्राइबल हाई स्कूल में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास किया और विशाल जनसभा में भाग लिया। एक ही दिन में 7 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तीन सड़कें और एक हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग। यह दिन असम के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा असम के गौहाटी से वर्चुअल माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के बाद विधायक पहले भेटारबंद ज़िप के धूपनपुर ट्राइबल हायर स्कूल की 4 करोड 50 लाख रुपये की लागत से नई इमारत का शिलान्यास किया। यह नई इमारत 2025-26 वित्तीय वर्ष के आर आई डी एफ प्रोजेक्ट के तहत होगी।

इसके बाद विधायक ने तीन ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया। यह तीनों सड़कें मुख्यमंत्री पकिपथ योजना के तहत बनाई जाएंगी। इन सड़कों में हैंः भेटारबंद जीपी की पूर्व फनाई से दौलतपुर तक की सड़क, जो 2025-26 वित्तीय वर्ष में 99 लाख रुपये की लागत से बनेगी। दूसरी सड़क भैरवबाड़ी से रांखल बस्ती तक 1 करोड 13 लाख रुपये की लागत से और तीसरी सड़क सिंगलाछड़ा जीपी के सी आर सड़क से पीएमजीएसवाई आबादी बस्ती रोड तक, 2025-26 वित्तीय वर्ष में 68 लाख रुपये की लागत से बनाई जाएगी। भेटारबंद जीपी के धूपनपुर ट्राइबल हायर स्कूल के शिलान्यास समारोह में बड़े जनसमूह को देखते हुए विधायक विजय मालाकार ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समय में असम सहित रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में विकास कार्य हुए हैं और रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विकास कार्य करना मेरा प्रथम कर्तव्य है लोगों के हित के लिए। समारोह में धूपनपुर ट्राइबल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य प्रदीप गोस्वामी, भेटारबंद जीपी के अध्यक्ष बिमल नाथ, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपी मोहन नाथ, एपी सदस्या सुस्रा दे, दुल्लभछड़ा मंडल बीजेपी के अध्यक्ष चंदन भर, जनरल सचिव नुपुर चक्रवर्ती, दुल्लभछड़ा और चैरेगी जिला परिषद सदस्य प्रणव मुखर्जी और पंकज राय शर्मा, पूर्व शिक्षक राजेंद्र बराई, लालछड़ा जीपी अध्यक्ष संजय गोस्वामी, दुल्लभछड़ा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष आलिम उद्दिन, वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा राज्यिक सदस्य उमा शंकर बनिया और अन्य विभिन्न मोर्चाओं के कार्यकर्ता समेत विशिष्ट व्यक्ति। इस दिन स्कूल की छात्राओं ने कार्यक्रम में सुंदर ढंग से धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश टीम में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव

● नए पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियाँ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली 7 दिनांकः 2 फरवरी 2026? पत्रकारों के हितों एवं संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली प्रदेश टीम में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय, महासचिव नरेंद्र भंडारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सक्सेना जी के निर्देशानुसार दिल्ली प्रदेश संगठन को मजबूत करने हेतु दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली इकाई में नए उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।इन बदलावों के तहत देवेन्द्र पवार को दिल्ली प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है।मुकेश मधुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।संजीव चौहान को संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया गया है

इस अवसर पर संजय सक्सेना जी को अन्य राज्यों के साथ दिल्ली प्रदेश टीम के संपर्क अधिकारी का दायित्व सौंपा गयासंजय सक्सेना जी को दिल्ली प्रदेश टीम का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।इसके अतिरिक्त संगठन को मजबूती देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे पदाधिकारियों में धर्मेंद्र भदौरिया (उपाध्यक्ष), नरेंद्र धवन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्वतन्त्र सिंह भुल्लर (उपाध्यक्ष),ईश मालिक उपाध्यक्ष जगजीत सिंह (प्रचार सचिव) तथाजितेंद्र दिवाकर प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर संगठन की बैठक में पत्रकारों की समस्याओं, उनके अधिकारों, सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य वातावरण एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श कर यह संकल्प लिया गया कि पत्रकारों की आवाज़ को मजबूती से सरकार और प्रशासन तक पहुँचाया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए अपेक्षा जताई कि सभी पदाधिकारी संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पत्रकार हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 97 जोड़ों का विवाह सम्पन्न

देवरिया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को ओम मैरेज हॉल, तरकुलवा में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 97 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया, जिसमें 83 हिन्दू एवं 14 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार की एक प्रभावी और संवेदनशील पहल है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता और सादगी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये व्यय किए जाते हैं, जिसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में, 25 हजार रुपये उपहार सामग्री तथा 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होते हैं। उन्होंने बताया कि अगला सामूहिक विवाह 4 फरवरी को प्रिंस पैलेस, देवरिया में आयोजित होगा, जिसमें 95 जोड़ों का विवाह प्रस्तावित है। योजना से जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक व आर्थिक संबल मिल रहा है।

दुष्कर्म मामले में दो गिरफ्तार

देवरिया। जनपद के लार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। थाना लार में पंजीकृत मुकदमा संख्या 30/2026 के तहत धारा 70(2), 351(3) बीएनएस एवं 5जी/5जे(2)/6 पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त शुभम सैनी निवासी थाना लार तथा एक बाल अपचारी को 2 फरवरी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को वादिनी ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री, जो कक्षा आठ की छात्रा है, को स्कूल के ही चार लड़कों द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म किया। मामले में विवेचना जारी है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।

शिवनगर में विश्व शांति के लिए नाम कीर्तन महोत्सव, यज्ञ, भंडारा का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। सिलापथार शिवनगर सर्वजनिन शिव मंदिर आंगन में आज से विश्व शांति के लिए अष्ट प्रहर यानी 24 घंटे अविराम नाम कीर्तन का एवं भंडारा का आयोजन किया गया है। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार गत कल शाम जलारूहण के बाद कुंज का उद्धाटन, भगवद गीता के पाठ किया गया। वैष्णवों द्वारा कलश की स्थापना के बाद, शिवनगर के नाम कीर्तन दल ने आदिवास कार्य संपन्न किया। महोत्सव सुबह 6 बजे हरे कृष्ण हरे राम नाम के जाप के साथ शुरू हुआ।

महोत्सव में अलीपुर नित्यानंद कीर्तन दल, कदमताल, चेंगाजान,सिलापथार के अद्वैत्य और गौर निताई कीर्तन दल ने नाम कीर्तन पेश किया। दोपहर 12 बजे दीनबंधु महंत बाबाजी के भोग लगाने के बाद महाप्रसाद वितरण किए गया। इस कार्यक्रम में इलाके के 3,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और महाप्रसाद लिया। उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष नाथ, सचिव प्रेमानंद नाथ ने मीडिया को दिए जानकारी अनुसार इस बार 44 संख्यक वर्ष में पदार्पण किया। ओर विश्व शांति के लिए हर वर्ष इलाके की लोगों की सहयोग में इस महोत्सव का आयोजन करते हुए आ रहे हैं, आज संपूर्ण रात नाम कीर्तन चलेगा कल सूर्योदय के बाद दही के भांड तोड़ कर नाम कीर्तन विराम दिया जाएगा एवं महंत विदाई अनुष्ठान संपन्न होगा।

परीक्षा सिर पर लेशन थीं तक हुई पढाई हाई स्कूल सलैया का मामला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल बिरसिंहपुर पाली- माध्यमिक शिक्षा मंडल व्दारा परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है जो कि 17 फरवरी से होने वाली है, लेकिन अध्यापन कितना हुआ, यह जानकर आप भौचक्के रह जायेगें। मामला हाई स्कूल सलैया 01 का है, जहाँ पर अभी तक अग्रेजी बिषय की कुल तीन लेशन तक पढाई हुई है। बताया जाता है की अग्रेजी बिषय के अध्यापन की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख प्राचार्य श्री मती मनोरमा सोनी जी सम्हाल रही है जो कि मूल रूप से कृषि विज्ञान वर्ग एक की शिक्षक है। विद्यालयो में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बिषय वार शिक्षको की पद संरचना की गयी है, जिस वजह से नियमत एक विद्यालय में शिक्षकों की तादाद भी निश्चित है, जिस वजह से सलैया विद्यालय में अग्रेजी बिषय की शिक्षक की भर्ती ही नहीं की गयी, जिस वजह से कृषि विज्ञान के शिक्षक से अग्रेजी बिषय पढाने की जिम्मेदारी उठा रही , इन्होंने जानबूझकर अग्रेजी बिषय के अतिथि शिक्षक की भर्ती ही नहीं की और न ही इस बात की जानकारी विभागीय अधिकारियों को देना उचित नहीं समझा। आखिर कार पूरे सत्र में सलैया विद्यालय में अग्रेजी बिषय का शिक्षक की नियुक्ति न कर विद्यालय में अध्ययन रत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।

प्राचार्य के साथ अतिथि शिक्षक की भी चल रही छुट्टी

सलैया विद्यालय में कक्षा नवमी में 30 छात्र और कक्षा 10 में 18 छात्र दर्ज हैं जहाँ पर सात शिक्षक पदस्थ है जिनमें तीन शिक्षक निमयित और चार अतिथि शिक्षक भर्ती किये गए हैं। इनमें से नरेश सोनी सहायक प्रयोग शाला शिक्षक भी लगातार अवकाश में बताये जाते हैं। मालूम होवे की अतिथि शिक्षक श्री सोनी विद्यालय के प्राचार्य के पति है, जिससे वह साल के अधिकांश दिनों में अवकाश में ही रहते हैं फिर भी उनका वेतन पूरे समय का आहरित किया जा रहा है। यह ओ डी भी बकायदा भरी जाती है। इस तरीके से विद्यालय शासन के नियमों से कम पारिवारिक संबंधों के आधार पर ज्यादा संचालित हैं। बताया जाता है कि इन दिनों संस्था की प्राचार्य विद्यालय से नदारद मिली और साथ में अतिथि शिक्षक नरेश सोनी और संगीता तिवारी भी विद्यालय में अनुपस्थित पायी गयी। नरेश सोनी के संबंध में बताया गया की वह लगभग एक पखवाड़े से अनुपस्थित है। प्राचार्य ने दूरभाष में बतलाया की हम पिछले दिनों से लगातार अवकाश में है और नरेश सोनी के लिये भी उन्होंने अवकाश की जानकारी दी।बताया जाता है कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस में भी प्रभारी प्राचार्य और अतिथि शिक्षक श्री सोनी जी सहित विद्यालय नहीं पहुंचे ?।

आयुक्त की जन सुनवाई में हुई शिकायत

सलैया विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय में अध्यापन कार्य के अपूर्ण होने की शिकायत कमिश्नर कार्यालय की जन सुनवाई में देते हुए कहा की विद्यालय में अग्रेजी बिषय का कोई शिक्षक ही पदस्थ नहीं है, जिससे अग्रेजी बिषय की पढ़ाई ही नहीं की गयी है। ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा में कुल एक पखवाड़ा शेष रह गए हैं और उस बिषय की पढ़ाई न होना न सिर्फ विद्यालय प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करता बल्कि पूरे अमले के ऊपर तीखे सवाल खड़े करके रख दिया है।

अब चलेगा नियमित और प्रायवेट का खेल

बोर्ड परीक्षाओं में नियमित छात्रों को प्रायवेट बनाने का खेल भी विद्यालयों में खूब फल फूल रहा है। बताया जाता है की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों को सुधारने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित हो रहा है, ताकि नियमित छात्रों की संख्या कम दर्शा कर अपने विद्यालय की नाक बचाने की कवायद की जाती है। साल भर विद्यालय में हाजिर होने वाले छात्रों को प्रायवेट बता कर संस्था प्रमुख अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं इसी कड़ी में सलैया विद्यालय में कुछ नियमित छात्रों को प्रायवेट बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सलैया विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन रत बैगा समुदाय की लक्ष्मी बैगा, अनिल बैगा, लक्ष्मण बैगा और देववतिया खैरवार को प्रायवेट छात्रों की श्रेणी में डाल दिया गया है जबकि कुछेक छात्र जिनकी उपस्थित अपेक्षाकृत कम है उन्हें नियमित छात्र के रूप में शामिल किया जा रहा है।

पुरुष सेपक टकराव ने टोक्यो में आयोजित एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम किया रौशन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष सेपक टकराव टीम ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों 2026 के टेस्ट इवेंट में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता। टीम को मुख्य कोच हेमराज द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री नरेश कुमार द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में आकाश युमनाम,संदीप कुमार,अरुण,राम कुमार,बॉबी कुमार और एस मालमंगबा सिंह शामिल थे,जिनके सामूहिक प्रयास और समर्पण ने देश को गौरव दिलाया।यह उल्लेखनीय उपलब्धि भारतीय सेपकटकरा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई,जो एशियाई स्तर पर टीम की बढ़ती ताकत और प्रतिस्पर्धी कद को दर्शाती है।

पेरिका सुरेश, संयुक्त सचिव,सेपक टाकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री एस.आर.प्रेम राज, अध्यक्ष, साउथ एशिया सेपक टकराव एसोसिएशन और सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री श्रीनिवासुलु ने टीम की सफलता पर बेहद खुशी व्यक्त की। उन्होंने भारतीय टीम को बधाई दी और आगामी 7 से 10 फरवरी 2026 तक कोलंबो में आयोजित होने वाली छठी दक्षिण एशियाई सेपक टकराव चैंपियनशिप के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं दीं। जॉइंट सेक्रेटरी सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुरेश ने कहा कि यह खेल लगातार लोकप्रियता का नया-नया मुकाम बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में भी यह खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा भारी संख्या में इस खेल से जुड़ रहे हैं।

48 घंटे में अवैध निर्माण नहीं हटा तो जेएनयू के हॉस्टल वार्डनों पर होगा एक्शन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की चेतावनी

नई दिल्लीः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने परिसर में अवैध निर्माण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय ने सभी हॉस्टल वार्डनों को निर्देश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर वार्डन फ्लैट और हास्टल परिसर के अंदर-बाहर किए गए किसी भी तरह के अवैध निर्माण को हटाएं। आदेश का पालन नहीं करने पर वार्डन के पद से हटाने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में डीन, छात्र कार्यालय की ओर से सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया गया।

सर्कुलर में कहा गया है कि हाल के दिनों में यह सामने आया है कि कुछ हास्टल वार्डन विश्वविद्यालय परिसर के भीतर और आसपास अस्थायी व स्थायी दोनों प्रकार के अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के आवास आवंटन नियमों का सीधा उल्लंघन है।

जेएनयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेएनयू परिसर में किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध है। विश्वविद्यालय की ओर से पहले भी इस विषय पर सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष तीन दिसंबर को भी कर्मचारियों और वार्डनों को अवैध निर्माण से बचने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था, इसके बावजूद ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आ रही हैं।

नए सर्कुलर में सभी हॉस्टल वार्डनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने वार्डन फ्लैट के अंदर और बाहर किए गए सभी अनधिकृत निर्माण को 48 घंटे के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों की अनदेखी करने पर विश्वविद्यालय नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप, समाजवादी पार्टी ने दी चेतावनी

देवरिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने आरोप लगाया है कि सत्तापक्ष फॉर्म-7 के दुरुपयोग के माध्यम से समाजवादी विचारधारा, पीडीए वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाताओं के मताधिकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यादव ने बताया कि फ़र्जी प्रपत्र, झूठे सत्यापन और प्रशासनिक दबाव के जरिए मतदाता सूची से नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें और बिना लिखित सहमति किसी को भी फॉर्म-7, फॉर्म-8 या अन्य प्रपत्र भरने की अनुमति न दें। उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता सूची से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ गंभीर अपराध है और इसमें शामिल कर्मचारियों व एजेंटों के खिलाफ एफआईआर, विभागीय निलंबन और न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।